other meat and meat processing facilities, tuna and other fish processing, setting up of cold chain, Research and development in food processing and packaging and training of manpower in certain sector; Assistance under these schemes can be availed by organisations/institutions in Bihar. Some assistance have already been availed by organisations in Bihar for setting up of Food Processing Training Centres for training of rural youth with a view to setting up of small food processing units.

Disposal of letters received from M.Ps

2307. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the Members of Parliament to his Ministy during the period from 1st April, 1990 to 31st March, 1993 alongwith year-wise details thereof;

(b) what is the number of letters out of them that were acknowledged;

(c) what is the number of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) what is the break-up of final letters issued by the Ministry containing positive and negative replies respectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) 1990-91 — 26

1991-92 — 19

1992-93 — 57

Total — 102

(b) 97

(c) 93

(d) Positive replies were sent in 74 cases and negative replies in 19 cases.

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश

2308. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का आंकलन करने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र मे निवेश की संभावनाओं का आकलन करने हेतु क्या विशिष्ट प्रयास किए गए हैं और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है । मंत्रालय की योजना स्कीम में राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन करने और आगे विकास करने के लिए सहायता देने की व्यवस्था है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी किसी सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है ।

तथापि जुलाई 1991 में उदारीकरण किए जाने के बाद से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है । अगस्त 1991 से जनवरी 1994 तक, उत्तर प्रदेश के लिए 515 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जिनमें 7,550 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाएगा, प्रस्तुत किए गए हैं प्रस्तावित पूंजी निवेश और रोजगार का उल्लेख करते हुए जनवरी, 1994 तक प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों का राज्यवार सारांश विवरण में दिया गया है ।

विवरण

जनवरी, 1994 तक प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों का राज्यवार सारांश

(हजार रूपयों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित निवेश
1.	आंध्र प्रदेश	145	30042	11235212
2.	असम	2	104	1780300
3.	बिहार	15	1454	1604630
4.	गुजरात	170	27929	24955301
5.	हरियाणा	305	56746	29265176
6.	हिमाचल प्रदेश	26	4563	2292865
7.	जम्मू और कश्मीर	7	810	207903
8.	कर्नाटक	53	5280	3016671
9.	केरल	14	2686	2408289
10.	मध्य प्रदेश	210	32369	18684732
11.	महाराष्ट्र	330	57529	70929669
12.	मणिपुर	0	0	0
13.	मेघालय	1	50	50000
14.	नागालैंड	1	140	8400
15.	उड़ीसा	11	2056	446100
16.	पंजाब	214	59676	29291088
17.	राजस्थान	256	42962	29515386
18.	तमिलनाडु	77	8489	5187607
19.	त्रिपुरा	0	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	515	97181	75501207
21.	पश्चिम बंगाल	53	8798	9175327
22.	सिक्किम	1	85	16000
23.	अंडमान निकोबार	1	260	45000
24.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
25.	चंडीगढ़	2	320	61905
26.	दादरा व नगर हवेली	5	312	185777
27.	दिल्ली	39	3540	862898
28.	दमन व दीव	4	382	75000
29.	एल.एम.एंड ए. द्वीप समूह	0	0	0
30.	मिजोरम	0	0	0
31.	पांडिचेरी	8	1211	206230
32.	गोवा	6	838	586825
	कुल जोड :	2471	445812	317595498